आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 10 (प्रति रविवार) इंदौर, 26 नवंबर से 02 दिसंबर 2023 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

मंडल और कमंडल की लड़ाई का रण भूमि बनेगा उत्तर प्रदेश

तमिलनाडु का जवाब यूपी में देंगे स्टालिन

वीपी सिंह के बारिस बने अखिलेश यादव

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय राजनीति में भारी उथल-पुथल मच गई है। बांटो और राज करो की जिस नीति पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण का जो खेल खेला था। इस नीति पर चलते हुए अब गैर भाजपाई दलों ने हिंदुओं के बीच सामाजिक ध्रुवीकरण करके कमंडल के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मंडल के मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति चेन्नई में लगवाई है। उन्होंने मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुलाया। वीपी सिंह के परिवार से उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी अनावरण में शामिल हुए। सामाजिक समरसता के नए समीकरण को लेकर हिंदुओं के बीच मंडल कमीशन की अखंड जगाने का काम स्टालिन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश से भारत का प्रधानमंत्री तय होता है। सनातन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और स्टालिन को निशाने पर लिया था। अब सनातन और ब्राह्मणवाद के विरोध में जाति समीकरण को लेकर हिन्दुत्व के शंखनाद

की तैयारी उत्तर प्रदेश से की जा रही है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लगातार ईड़ी की कार्रवाई जारी रखी थी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार को असफल बनाने के लिए कई बिल रोक कर रखे थे। हैरान परेशान स्टालिन ने भी अब केंद्र की मोदी सरकार को उन्ही की स्टाइल में जवाब दे दिया है। तमिलनाडु सरकार ने करोड़ों रुपए के विज्ञापन अखिलेश यादव और बीपी सिंह की मूर्ति को लेकर सारे देश के प्रमुख अखबारों में जारी किए हैं। खुलकर वह अब केंद्र सरकार के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं।

रही सही कसर कांग्रेस पूरी कर रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग करते हुए, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। वहां जाति जनगणना शुरू करने और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हिस्सा कहकर सामाजिक समीकरण का नया दांव चल दिया है। जिसके कारण हिंदू वोटो में खंड-खंड में बंटवारे की स्थिति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के की कमंडल की राजनीति के लिए एकाएक चुनौती खड़ी हो गई है।

दक्षिण भारत में इरोउ बेंकट रामास्वामी दक्षिण के राज्यों में पेरियार के नाम लोकप्रिय हैं। उन्होंने 20वीं सदी में दलित, शोषित एवं गरीबों के लिए ब्राम्हणबाद से लड़ाई लड़ी थी। गैर बराबरी वाले हिन्दुत्व का विरोध किया था। दक्षिण में महात्मा गांधी की तरह लोकप्रिय हैं। उत्तर भारत से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन के माध्यम से उत्तर भारत में गैर बराबरी वाले हिन्दुत्व के बीच में समानता लाने के लड़ाई शुरु की थी।

इंडिया गठबंधन को लेकर संशय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और राहुल गांधी प्रियंका गांधी का कद बढ़ रहा था। दलित और मुस्लिम कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे थे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनदेखी की। उसके बाद वह भी यूपी और देश में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तीसरे मोर्चे की तर्ज पर एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी है। इसका अंजाम किस तरह का होगा, अभी कहना मुश्किल है। इतना तय है, कि 2024 के लोकसभा चुनाव का महासंग्राम उत्तर प्रदेश की रणभूमि में होना तय है।

तमिलनाडु से लड़ना चाहते थे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध चरम सीमा पर है। पेरियार वहां के सर्वमान्य नेता हैं। अन्ना डीएमके और डीएमके दोनों ही पेरियार के बताए हुए मार्ग पर राजनीति कर रहे हैं। सनातन को लेकर जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। उसका जवाब अब सभी विपक्षी दल मिलकर सामाजिक समरसता के रूप में देने जा रहे हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की 80 फ़ीसदी आबादी धार्मिक एवं सामाजिक आधार पर बटी हुई है। ब्राह्मणवाद को शोषण का प्रतीक माना जाता है। ब्राह्मणवाद की पहचान ही सनातन के रूप में है। जिसके कारण यह कहा जा सकता है, कि इस बार का लोकसभा चुनाव धर्म युद्ध की तरह होगा। इस धर्म युद्ध की शुरुआत कमंडल से शुरू हुई थी। अब मंडल आकर इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगा।

बच्चों का सिलेबस क्या हो, यह तय करना सरकार का काम : सुको

नई दिल्ली। स्कूली में बच्चों को क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना यह सरकार का काम है, इस संबंध में कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकती है। बता दें कि हार्ट अटैक से जान बचाने में कारगर सीपीआर तकनीक को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर एक याचिका लगाई थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका में की गई मांग सरकार के नीतिगत मसलों के तहत आती है। सरकार को तय करना है कि स्कूली बच्चों का पाठ्यक्रम क्या हो। ऐसी अनगिनत चीज़े हो सकती हैं जिनकी जानकारी बच्चों को पढ़ाई के दौरान ही होनी चाहिए पर कोर्ट अपनी ओर से उन सब को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश नहीं दे सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने

याचिकाकर्ता से कहा कि इस बाबत आप चाहें तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। बता दें कि सीपीआर सिखाने की मांग करने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हाल के समय में हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में बच्चों को हृदय रोग संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। याचिका में आपातकालीन स्थिति में सीपीआर के जरिए मरीज की सहायता कैसे की जाए, इसकी भी मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि बच्चे क्या पढ़ें, यह हम तय नहीं कर सकते। बताया गया कि बीते कुछ महीनों से ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें स्कूली बच्चे भी हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं।

इसी साल पिछले सितंबर माह में लखनऊ के सिटी मांटेसरी स्कूल में नौवीं कक्षा के एक छात्र की अचानक मौत हो गई थी। उस छात्र की मौत को भी हार्ट अटैक से मौत माना गया था। इसी तरह अक्टूबर के महीने में राजस्थान के बीकानेर में एक मासूम की देखते ही देखते तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। इस तरह के कई और मामले देखे गए हैं।

धार्मिक छुट्टियों में सभी बच्चों का समान अधिकार-एनसीपीसीआर

नई दिल्ली। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव के मुद्दे को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गंभीरता से लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने सभी बच्चों को धार्मिक उत्सव मनाने का समान अवसर उपलब्ध कराने को कहा है। उसने सात दिन के भीतर इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। बिहार सरकार पर स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करने और उसकी जगह मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाने का आरोप है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संधि का हस्ताक्षरकर्ता है और उसके तहत बच्चों को दिये गए सहभागिता के अधिकार के संरक्षण की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर पाक्सो और जुवेनाइल जस्टिस कानून से जुड़े मामलों की निगरानी के साथ ही मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के उचित क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी है। बिहार सरकार का छुट्टियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संधि के साथ ही आरटीई का भी उल्लंघन है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सात दिन के भीतर यदि जवाब नहीं मिलता है तो आयोग उन्हें तलब करने के लिए समन भी भेज सकता है। इसके पहले भी आयोग बिहार के किशनगंज और अन्य सीमावर्ती इलाकों के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी करने पर नोटिस भेज चुका है।

संपादकीय

भूतों से ज्यादा भय, अब ईड़ी के नोटिस का

केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों और कार्य प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा चल रही है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा आरोप के आधार पर बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ईड़ी द्वारा जारी नोटिस पूर्णताऱ्अस्पष्ट होते हैं। जिस तरह से लोग भूत का नाम सुनकर डरने लगते हैं। ठीक वही स्थिति आज ईड़ी की हो गई है। भूतों के चंगुल से झाड़ फूंक कर कर भले निजात मिल जाए। लेकिन ईड़ी के जाल में फंसे तो पूरा केरियर, मान प्रतिष्ठा ही बर्बाद हो जाती है। तमिलनाडु राज्य के ।0 कलेक्टरों को ईड़ी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में 10 कलेक्टरों ने याचिका दायर की है। जिसमें ईड़ी द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। ईड़ी के अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं, कि वह अपनी सीमा से परे जाकर नोटिस जारी कर लोगों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो ईड़ी के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिए जाने की शिकायतें भी बड़ी आम हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर सुनवाई के दौरान ईड़ी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कि वह जो भी नोटिस जारी करते हैं। उसमें किस मामले में नोटिस जारी किया गया है। जिसे नोटिस जारी किया गया है, उसे गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है, या आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है। किस मामले में उससे पूछताछ की जानी है। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। इन निर्देशों का पालन भी ईड़ी के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली कई सुनवाई में कहा गया है, मनी लांड्रिंग के मामलों में ईड़ी को विशेष शक्तियां दी गई हैं। लेकिन देखा जा रहा है, कि ईड़ी उन मामलों में भी सीधे हस्तक्षेप कर रही है, जिनका मनी लांड्रिंग से कोई लेना देना नहीं है। सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, की तर्ज पर चलते हुए ईड़ी के अधिकारी न्यायपालिका को भी नजर अंदाज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ।8 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि वह पीएमएलए के प्रावधानों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। उस समय सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार द्वारा एक माह का समय मांगा गया था। समय देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस मामले की सुनवाई चल रही थी। ऐसे समय पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुनवाई को टालने के लिए कहा, याचिकाकर्ताओं के संशोधनों का जवाब देने समय मांग लिया। केंद्र सरकार के यह कहे जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई टालनी पड़ी। न्यायमूर्ति संजय किशन कोल अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। जिसके कारण अब नई खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।केंद्र सरकार इस मामले की सुनवाई नहीं कराना चाहती है, इसलिए तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख,मांग रही है। बहरहाल ईड़ी द्वारा जिस तरह से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। छापे डाले जा रहे हैं। आरोपियों की संपत्तियां जप्त की जा रही हैं।उससे ईड़ी का इतना भय बन गया है, कि हर आदमी ईड़ी के नोटिस और उससे बचना चाहता है। ईड़ी का जो भय बन गया है, उसको लेकर ईड़ी के अधिकारी अब रिश्वत की वसूली के काम में भी लग गए हैं। एक मामला तो खुद सीबीआई ने पकड़ा है। दूसरा मामला राजस्थान की पुलिस ने ईड़ी के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चुनाव के समय चुनाव वाले राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं, उनसे जुड़े हुए कारोबारी, अधिकारियों के यहां जिस तरह से नोटिस जारी कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इन सब मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई मामला ही नहीं होता है। भ्रष्टाचार या अनिमियता के आरोप में ईड़ी नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर देती है। मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी जिस तरह से न्यायपालिका हाथ भी पर हाथ बांधकर बैठी हुई है। उससे लोगों के मन में, निराशा का भाव है।

सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने स्वयं कहा, कि मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई सबूत, ईड़ी अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। उसके बाद भी मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत न देकर,एक तरह से सरकार की इच्छा पूरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में ट्रायल पूरा करने का आदेश देकर सरकारऔर ईड़ी के अधिकारियों की मदद ही की है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। अंग्रेजों के बने हुए कानून में भी 90 दिन के अंदर जांच अधिकारी को चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होती थी। सारे सबूत अदालत में पेश करना होते थे। जांच एजेंसी यदि यह नहीं कर पाती थी, तो कोर्ट जेल में बंद आरोपी को सो मोटो जमानत देकर जेल से रिहा कर देती थी। अब लोग कहने लगे हैं, कि वर्तमान में जो पीएमएलए का कानून बना है। उसने अंग्रेजों के बनाये को भी मात दे दी है।

चुनावी-भ्रष्टता पर नियंत्रण के लिये जटायुवृत्ति जागे

ललित गर्ग

चुनाव लोकतंत्र की जीवनी शक्ति है, यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है, लोकतंत्र में स्वस्थ मूल्यों की स्थापना के लिये चुनाव की स्वस्थता एवं उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत एवं मूल्यहीन होने से लोकतंत्र की जड़े तो खोखली होती ही है, राष्ट्र भी मूल्यहीनता की ओर अग्रसर होता है। चरित्र-शुद्धि के अभाव में चुनाव शुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, रेवड़ी-संस्कृति, लोकलुभावने वायदों और गारंटियों का जो कोलाहल सुना जा रहा है, येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की होड़ देखने को मिल रही है, जो कालांतर में देश के सशक्त होने, आर्थिक अनुशासन व योग्य जनप्रतिनिधियों के चयन के लिये एक चुनौती बन सकता है। लगातार चुनावों में मुक्त की रेवड़िया बांटने की परम्परा ने चुनाव प्रक्रिया एवं उसके आदर्श को धुंधलाया है। यह विडंबना है कि लोग जनप्रतिनिधि की योग्यता, कर्मठता, चारित्रिक उज्ज्वता की प्राथमिकता को दरकिनार करके संकीर्ण सोच के लाभों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इस दूषित परंपरा से राजनेताओं और जनता का प्रलोभन विस्तार ले रहा है। इस बढ़ती बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलिया डालना अपनी जिम्मेदारी से पलायन है, इसके विरोध में व्यापक जन-चेतना जगाने की अपेक्षा है। आज चुनाव में बढ़ता भ्रष्टाचार का रावण मानवता एवं चुनाव शुद्धि की सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, सब यह अनर्थ होते हुए देख रहे हैं, पर कोई भी जटायु आगे आकर उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। चुनाव-भ्रष्टाचार के प्रति जनता, राजनीतिक दलों एवं नेताओं का यह मौन, यह उपेक्षाभाव उसे बढ़ायेगा नहीं तो और क्या करेगा?

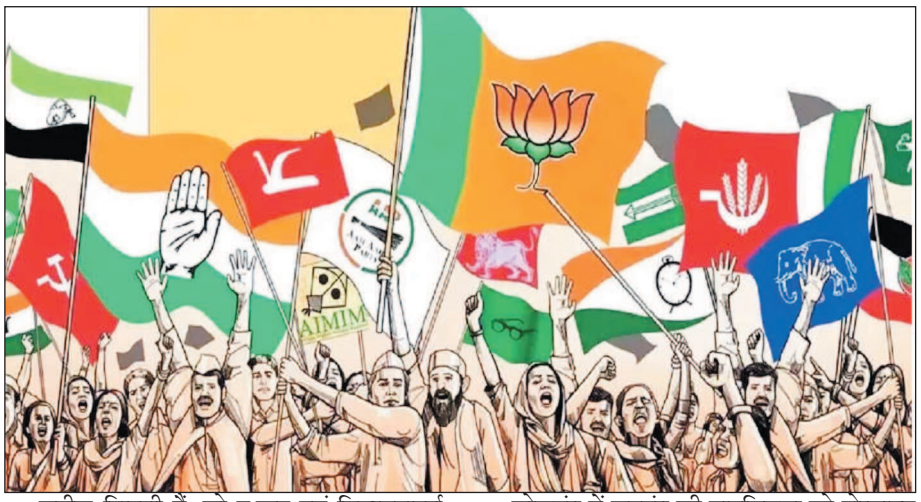

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। अब केवल तेलंगाना में मतदान होना शेष है। इन राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान यह बात और उभरकर सामने आई कि मतदाता राजनीतिक दलों के प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार है और राजनीतिक दल एवं उनके उम्मीदवार मतदाताओं को ठगने, लुभाने एवं गुमराह करने की होड़ में लगे हैं। 'गरीब की थाली में पुलाव आ गया है...लगता है शहर में चुनाव आ गया है' भारत की राजनीति एवं चुनावों पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं, जो दुःखद एवं विडम्बनापूर्ण है। आम तौर पर मतदाता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में यह नहीं देखता कि उसमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार, नागरिक सुविधाएं, बिजली-पानी आदि के ठोस वादे किए गए हैं या नहीं? वह अब यह देखता है कि किस दल ने उन्हें क्या-क्या मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने के वादे किए हैं। वक्त की जरूरत है कि मतदाताओं को लालीपॉप देने, मुक्त की रेवड़िया बांटने के बजाय उन्हें ऐसे अवसर दिये जाने चाहिए ताकि वे कालांतर आत्मनिर्भर बन सकें, सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके, देश के सशक्त आर्थिक विकास में योगभूत बन सके।

भ्रष्ट चुनाव से तो भ्रष्ट नेतृत्व ही मिलेगा, ऐसी भ्रष्ट स्थितियों से देश के आर्थिक विकास में भी भ्रष्टता ही व्यापक होगी, शासन के सामने आर्थिक चुनौतियें खड़ी होगी। इस तरह मुफ्त की योजनाओं और गारंटियों से सिर्फ हमारा राजकोषीय घाटा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार को पनपने का खुला मौका मिलेगा। मतदाता यदि किसी राजनीतिक दल की दूरगामी नीतियों व विकास योजनाओं को नजरअंदाज करके तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देगा तो भविष्य में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उम्मीदवारों के षड़यंत्र एवं मतदाताओं के लोभ हमारी चुनाव प्रक्रिया को भी संकट में डालते हैं। जाहिर बात है कि मुफ्तखोरी की संस्कृति के बूते सत्ता में आने वाला नेता कालांतर में सरकारी संसाधनों के दोहन को अपनी प्राथमिकता बनायेगा। जो धन उसने चुनाव के दौरान बांटा है उसका कई गुना येन-केन-प्रकारेण वसूलेगा। जिससे लोकतंत्र में लूटतंत्र की मानसिकता को प्रोत्साहन मिल सकता है। चुनाव में मुफ्त रेवड़ी संस्कृति के साथ चुनाव का अधिकाधिक खर्चीला होना भी गंभीर चिन्ता का विषय है। एक-एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने में करोड़ों रूप्ये व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं जायज-नाजायज तरीकों से प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं भ्रष्टता की परम्परा का सिंचन मिलता है। यथार्थ में देखा जाये तो जनमंत्र अर्थतं. बन कर रह जाता हैं, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। ऐसे में ईमानदार, योग्य एवं कर्मठ लोगों का राजनीति में आने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। चुनावों में लगातार बढ़ रही भ्रष्टता की नाजुक स्थिति में व्यक्ति-व्यक्ति की जटायुवृत्ति को जगाया जा सके, चुनावी भ्रष्टाचार के विरोध में एक शक्तिशाली समवेत स्वर उठ सके और उस स्वर को स्थायित्व मिल सके तो लोकतंत्र की जड़ों को सिंचन मिल सकता है और ऐसे हालातों में भी हमारा अमृत-काल भी चुनाव-प्रक्रिया के लिये भी अमृतमय बन सकता है।

इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त पेशकश के मामले में होड़ करके राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने में लगे रहे। चुनाव में रेवड़ियों की इस बारिश के राजनीतिक एवं आर्थिक, दोनों निहितार्थ हैं। साथ ही यह उन राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये को भी जाहिर करता है जो मुफ्त पेशकश के मामले में दूसरे दलों को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए खुद उनका सहारा लेने से कोई संकोच नहीं करते। यह दोहरा रवैया भाजपा के चरित्र में भी समाया है। सही मायनों में मुफ्त के उपहारों की हमेशा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह हमारे लोकतंत्र की भी विफलता है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी हम अपने लोकतंत्र को इतना सजग व समृद्ध नहीं बना पाये कि मतदाता अपने विवेक से अपना दूरगामी भला-बुरा सोचकर मतदान कर सके। अतीत के अनुभव बताते हैं कि जिस भी राज्य ने मुफ्त खाद्यान्न, पानी, बिजली व सब्सिडी बांटी है उसकी अर्थव्यवस्था भविष्य में चरमराई ही है। सही मायनों में मुफ्त कुछ नहीं होता, वह करदाताओं की पसीने की कमाई से पैदा होता है। देश को कल्याणकारी नीतियों की जरूरत है, लेकिन वह आर्थिक अनुशासन और राजकोषीय विवेक पर आधारित होना चाहिए।

कोई भी दल यह बताने को तैयार नहीं कि वे मुफ्त वस्तुएं जैसे कि स्कूटी, लैपटाप, मोबाइल, सोना, मुफ्त बिजली-पानी-बस यात्रा समेत अन्य वस्तुएं और सुविधाएं देने के जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे? वास्तव में यह वह सवाल है जो मतदाताओं को करना चाहिए। वह यदि यह सवाल नहीं करता तो इसका कारण लालच और फौरी लाभ ही है। लेकिन मतदाताओं का यह लाभ का दृष्टिकोण समूचे लोकतंत्र के लिये कितना नुकसानदायी है, इस पर चिन्तन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रेवड़िया बांटने का खेल देश में पहले नहीं होता था, लेकिन आज जिस पैमाने पर हो रहा है, वह हर देशभक्त की चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं न कहीं, मुफ्त की गारंटियों का यह खेल जवाबदेह प्रशासन व आर्थिक स्थिरता पर कालांतर गहरी चोट करेगा। वहीं ये गतिविधियां एक जिम्मेदार लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाती हैं। यह बड़ा सत्य है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से हमारी अर्थव्यवस्था व विवेकशील सुशासन पर घातक असर पड़ता है। अंततः रेवड़ी संस्कृति का आर्थिक दबाव सरकारी संसाधनों पर पड़ता है। राज्यों के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। ऐसे में बांटा गया धन कालांतर में हमारे बुनियादी ढांचे व विकास परियोजनाओं के लिये निर्धारित धन में कटौती करता है। जिससे समग्र एवं संतुलित विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। निश्चित रूप से समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक संबल दिया जाना चाहिए।

इन्दौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव सीओपी-28 दुबई में विशेष रूप से आमंत्रित

इन्दौर। नम्बर वन शहर इन्दौर के लिए यह एक और गर्व की बात है कि इन्दौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव को सीओपी-28 प्रेसीडेंसी और ब्लूमबर्ग फ़िलैंथ्रोपीज़ द्वारा संयुक्त रूप से दुबई में आयोजित किए जाने वाले शिखर सम्मेलन में क्लीन एयर कैटलिस्ट के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार सहित लोकल क्लाइमेट एक्शन में इंदौर के योगदान पर प्रजेंटेशन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई राष्ट्र प्रमुख विश्व नेता शामिल होंगे। विश्व जलवायु परिवर्तन विषय पर चर्चा को लेकर आयोजित इस शिखर सम्मेलन कॉप28 में भाग लेने इन्दौर मेयर 30 नवंबर को दुबई पहुंचेंगे। भारत की बेस्ट स्मार्ट

सिटी मे से एक इंदौर ने वायु गुणवत्ता सुधार, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसे मोर्चों पर बड़ी सफलता हासिल की. है। सम्मेलन में भार्गव लोकल क्लाइमेट एंक्शन समिट में इंदौर की इस सफलता और अनुभवों को साझा करेंगे। इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन सीओपी-28 में इंदौर का नाम रोशन होगा। भार्गव के अनुसार सीओपी-28 में मैं इंदौर के मौजूदा क्लाइमेट टारगेट्स की जानकारी देते हुए बताउंगा कि हम साझेदारी और सहयोग के जरिये इन्हें कैसे हासिल करेंगे। इसमें इंदौर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्लीन एयर कैटलिस्ट के साथ साझेदारी और सहयोग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तौर-तरीकों का जिक्र शामिल होगा।

मतगणना शुरू होने के एक घंटे पहले कर्मचारियों को पहुंचना होगा स्टेडियम

30 नवंबर को दिया जाएगा, कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण

2561 ईवीएम के मतों की गणना के लिए 143 टेबलें लगेंगी

इंदौर। जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के मतों की गिनती तीन दिसंबर को नेहरू स्टेडियम के नौ कक्षों में की जाएगी। सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी। इसके बाद ईवीएम के मतों की गणना शुरू होगी। मतदान कर्मियों को एक घंटा पहले स्टेडियम पहुंचना होगा। प्रवेश के लिए आदेश की कापी और एक आइडी प्रूफ रखना अनिवार्य किया गया है। मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे। 2561 ईवीएम में बंद 20.32 लाख से अधिक मतों की गणना के लिए 143 टेबलें लगाई जाएंगी।

मतगणना के लिए नियुक्त कर्मचारियों को 30 नवंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा । इसें ईवीएम की गणना 516 और डाक मतपत्रों की गणना 180 कर्मचारी करेंगे। इन्हें मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक, माइक्रो आब्जर्वर और पोस्टल बैलेट की गिनती का दायित्व सौंपा जा रहा है। सभी का पहला प्रशिक्षण हो चुका है व 32 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम के माध्यम से मतगणना के तरीके बताए। डाक मतपत्र के लिए 37 टेबल- जिले में डाक मतपत्रों के लिए 37 टेबलें लगाई जाएगी। देपालपुर में तीन, इंदौर-1 में चार, इंदौर-2 में चार, इंदौर-3 में चार, इंदौर-4 में चार, इंदौर-5 में पांच, महू में चार, राऊ में पांच और सांवेर चार टेबल रहेगी।

कैमरों में कैद होगी प्रक्रिया मतगणना के लिए नौ कक्ष बनाए गए हैं। मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। प्रत्येक टेबल पर क्या हो रहा है। इसकी पूरी रिकार्डिंग कैमरों में कैद होगी, ताकि मतगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी भी तरह के विवाद में कैमरों में रिकार्ड प्रक्रिया को देखा जा सके।

पल्स पोलियो अभियान 10 से, जिले में 5 लाख बच्चों को पिलाएंगे दवा

इंदौर। जिले में पल्स पोलियो अभियान 10 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें 5 साल तक के 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि पहले दिन टीकाकरण बूथों पर दवा पिलाई जाएगी। 11 व 12 दिसंबर को स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर दवा देंगे ताकि कोई भी बच्चा वंचित न रहे। भारत में 2011 के बाद पोलियो का एक भी केस नहीं मिला। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। हालांकि अफगानिस्तान व पाकिस्तान में नए केस मिलने के बाद भारत में एहतियात के तौर पर यह अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। 10 दिसंबर को 3500 से अधिक बथ और 8 हजार से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर 24 घंटे बथ लगेगा।

बैठक में अपर कलेक्टर गौरव बेनल, जिपं के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर रोशन राय, निशा डामोर, राजेंद्र रघुवंशी, सीएमएचओ डॉ. बीएस सैत्या, सिविल सर्जन डॉ. एसएल सोढ़ी मौजूद थे।

कांग्रेस प्रत्याशियों ने भोपाल में ली मतगणना ट्रेनिंग

तय समय से पहले मतगणना स्थन में पहुंचने की हिदायत

इंदौर। मप्र के विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मतगणना के लिए रविवार को कांग्रेस ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल में ट्रेनिंग दी थी। इसके लिए इंदौर से भी सभी प्रत्याशी को भोपाल बुलाया गया था। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान सभी प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई है कि मतगणना के दौरान कैसे सावधानी बरतनी है।

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने अपने प्रत्याशियों, सहयोगियों के लिए रविवार को रखें प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया कि समय से पहले अपने तय स्थान पर पहुंच जाएं। सूत्रों ने बताया कि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सभी से लाइव चर्चा करते हुए कहा था कि मतगणना का काम किसी भी दबाव के साथ ना करें। वहीं प्रत्याशियों को यह भी बताया गया कि मतगणना शुरू होने से पहले संयम और सक्रियता से कार्य को अंजाम दें। मतदान के दिन जो ईवीएम सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई, उसका निरीक्षण करें। कोई त्रुटि पाए जाने पर निर्वाचन अधिकारी को सूचना दें। मतगणना शुरू होते ही मतगणना के हर राउंड और एक-एक मतों पर पैनी नजर रखें। डाक मत पत्रों की गिनती पर विशेष निगाह रहे। बता दें कि इंदौर के सभी प्रत्याशी ट्रेनिंग लेने के बाद देर रात ही इंदौर लौट आए थे।

दो चरणों में हुआ ट्रेनिंग सेशन-

भोपाल में आयोजित ट्रेनिंग दो शिफ्टों में दी गई थी। सुबह 11 बजे से शुरू हुई पहली शिफ्ट में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर-चंबल संभाग के कांग्रेस प्रत्याशियों की ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं दूसरी शिफ्ट 2.30 बजे से शुरू हुई थी। जिसमें इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग के प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई थी।

6 वर्षीय मासूम का हार्ट फेल, मौत

इंदौर। इंदौर के कंचनबाग में रहने वाले छह वर्षीय विहान जैन की दिल्ली में मौत हो गई। कारोबारी राहुल जैन का इकलौता बेटा विहान पहली कक्षा में पढ़ता था। परिवार का कहना है कि उसे कमजोरी आने पर दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट किया था। यहां उसे कार्डियक अरेस्ट आया और मौत हो गई। रविवार को उसका इंदौर में अंतिम संस्कार किया गया।

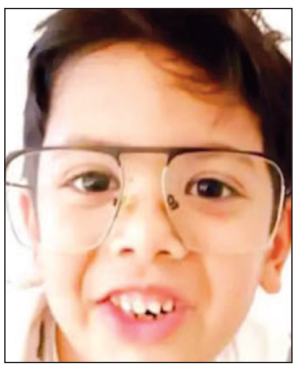

पिता राहुल जैन ने बताया- विहान दो दिन से अस्वस्थ था। उसका शरीर तप रहा था, लेकिन जब थर्मामीटर से देखा तो बुखार नहीं था। इंदौर में इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गया, लेकिन कुछ कमजोरी थी। इसके बाद परिवार में एक कार्यक्रम होने के कारण सभी दिल्ली गए थे। यहां कमजोरी महसूस करने पर विहान को स्थानीय डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। उसे हॉस्पिटल ले गए तो आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका।

हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने परिजन को बताया- विहान के ब्लड टेस्ट में उसके मायोकार्डाइटिस से पीड़ित होने का पता चला था। यह बीमारी सीधे हार्ट पर असर करती है। इसी से उसकी मौत हुई है।

मायोकार्डाइटिस-हृदय की मांसपेशियों में सूजन की स्थिति-कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एडी भटनागर के मुताबिक, मायोकार्डाइटिस या मायोकार्डियम हार्ट की मांसपेशियों में सूजन की स्थिति है। सूजन के परिणामस्वरूप हार्ट के खून को पंप करने की क्षमता को नुकसान हो सकता है। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और तेज या अनियमित दिल की धड़कन, ये सभी मायोकार्डाइटिस (अतालता) के लक्षण हैं।

मायोकार्डाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण हो सकता है। यह दवा की प्रतिक्रिया या सामान्य सूजन संबंधी बीमारी के कारण भी हो सकता है। गंभीर मायोकार्डाइटिस हार्ट को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर के बाकी हिस्सों में अपर्याप्त रक्त प्रवाह होता है। दिल में थक्के के कारण स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ सकता है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सरिता राव ने बताया- मायोकार्डाइटिस हार्ट अटैक नहीं है। चिकित्सकीय भाषा में कहें तो यह इनफ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम है। यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। सामान्य बुखार में भी कई बार वायरस हार्ट पर अटैक कर देता है।

जिससे हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है और हार्ट फेल हो जाता है। यह वायरल इंफेक्शन होता है। यह रिवर्सेबल भी हो जाता है। जब बीमारी का एक्यूट फेज निकल जाता है तो मरीज में सुधार आ जाता है।

मायोकार्डाइटिस हार्ट अटैक से अलग होती है। यह हार्ट की मसल्स को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से बुखार में कभी सांस नहीं फूलती लेकिन ऐसा हो तो तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

2018 में प्रदेश की 13 सीटों पर नोटा ने बिगाड़ दिया था भाजपा-कांग्रेस की जीत का गणित

10 सीटें भाजपा को नोटा ने हरवा दी थी

भोपाल। यदि वोटर्स को उम्मीदवार पसंद नहीं और उसने नोटा दबा दिया तो, उम्मीदवार को कितनी मुश्किल हो सकती है, इसका अंदाज 2018 के हार-जीत के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। इस चुनाव में नोटा ने प्रदेश की 13 सीटों पर भाजपा-कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत का गणित बिगाड़ दिया था। ये वो सीटें थीं जहां नोटा उम्मीदवारों की हार-जीत का अंतर नोटा के वोटों से कम रहा था।जबकि नोटा में ज्यादा वोट पड़े थे। कहने का मतलब है कि 2018 के चुनाव में नोटा से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ था। भाजपा 10 सीटों पर सिर्फ नोटा की वजह से हार गई थी। इसमें सबसे कम अंतर की जीत 121 वोटों की ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर रही थी। यहां नोटा को 1150 वोट मिले थे।

नोटा की वजह भाजपा ये 10 सीटें हार गई थी

- जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पर पूर्व राज्यमंत्री शरद जैन को 578 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। इस सीट पर मतदाताओं ने 1209 वोट नोटा को दिया था। इस सीट से कांग्रेस के विनय सक्सेना ने जीत दर्ज की थी।
- जोबट विधानसभा सीट पर हार-जीत का अंतर 2056 वोटों का था। इस सीट से कांग्रेस की कलावती भूरिया ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 46067 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के माधौसिंह डाबर को 44011 वोट मिले थे। जबकि नोटा को 5139 वोट मिले थे।
- नेपानगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार भी नोटा की वजह से हार गए थे। उनकी हार 732 वोटों से हुई थी, लेकिन नोटा में 2551 वोट गए थे। इस सीट से कांग्रेस की सुमित्रा देवी कासडेकर ने चुनाव जीता था।
- सुवासरा विधानसभा सीट पर भाजपा के राधेश्याम पाटीदार कांग्रेस के हरदीप डंग से सिर्फ 350 वोटों से हार गए थे। यहां नोटा को 2976 वोट मिले थे।

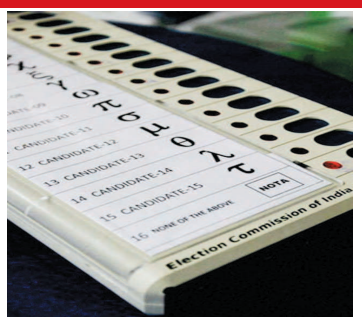

- दमोह सीट पर भी जीत-हार के अंतर से ज्यादा नोटा के खाते में वोट थे. यहां नोटा को वोट मिले थे 1299, जबकि जीत-हार का अंतर था 798 वोटों का. यहां कांग्रेस के राहुल सिंह चुनाव जीते थे।
- ब्यावरा विधानसभा सीट पर नोटा के खाते में आए थे 1481 वोट, जबकि जीत-हार का अंतर 826 वोटों का था। यहां से कांग्रेस के गोवर्धन दांगी ने चुनाव जीता था।
- मांधता सीट पर हार-जीत का अंतर सिर्फ 1236 वोटों का हुआ था। यहां भाजपा के नरेन्द्र तोमर कांग्रेस के नारायण पटेल से हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार को 71 हजार 228 वोट और भाजपा को 69992 वोट मिले थे। जबकि 1575 वोटर्स ने नोटा दबाया था।
- राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बाला बच्चन 932 वोटों ने जीत दर्ज की थी। यहां से भाजपा के उम्मीदवार अंतर सिंह पटेल चुनाव हार गए थे। यहां 3358 लोगों ने नोटा दबाया था।
- गुन्नौर विधानसभा सीट पर भी हार-जीत का अंतर सिर्फ 1984 वोटों का था। जबकि 3734 वोटर्स ने नोटा दबाया था। इस सीट से कांग्रेस के शिवदयाल बागरी चुनाव जीते थे।
- इसी तरह से ग्वालियर दक्षिण सीट पर हार-जीत का अंतर बेहद कम रहा। यहां भाजपा के नारायण सिंह कुशवाहा कांग्रेस के प्रवीण पाठक से सिर्फ 121 वोटों वोटों से हार गए थे। इस सीट पर 1150 वोटर्स ने नोटा दबाया था।

नोटा की वजह से कांग्रेस ये सीट हार गई थी

- जावरा विधानसभा सीट पर हार-जीत के अंतर से ज्यादा नोटा के वोट थे। यहां नोटा पर 1510 मतदाताओं ने वोट डाला था, जबकि हार-जीत का अंतर 511 वोटों का था। इस सीट से भाजपा के राजेन्द्र पांडेय चुनाव जीते थे।
- कोलारस विधानसभा सीट पर जीत-हार का अंतर 720 वोटों का था। जबकि नोटा के खाते मे गए थे 1674 वोट। इस सीट पर भाजपा के वीरेन्द्र रघुवंशी चुनाव जीते थे।
- बीना विधानसभा सीट पर जीत-हार का अंतर सिर्फ 460 वोटों का था। जबकि 1531 वोटर्स ने नोटा पर बटन दबाया था। इस सीट पर भाजपा के महेश राय ने जीत दर्ज की थी।

इनके खिलाफ मतदान में पक्षपात और गड़बड़ी की शिकायतें

आठ कलेक्टर, छह एसपी सहित तीन दर्जन अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश में 3 दिसंबर के बाद सरकार भाजपा-कांग्रेस में किसी भी पार्टी की बने, लेकिन प्रदेश के 8 जिला कलेक्टर, 6 एसपी सहित प्रदेश के तीन दर्जन अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। इन अधिकारियों के खिलाफ मतदान के दौरान पक्षपात और गड़बड़ी की चुनाव आयोग में शिकायतें की गई हैं। भाजपा ने चुनाव के दौरान चार जिला कलेक्टरों पर चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने और सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। जबकि कांग्रेस ने आठ कलेक्टरों पर भाजपा का एजेंट होने और चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इनमें नरसिंहपुर, छतरपुर और भिंड कलेक्टर के खिलाफ भाजपा ने भी शिकायत की है। इनके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के दो दर्जन अधिकारियों के खिलाफ भी चुनाव के दौरान पक्षपात एवं लापरवाही की शिकायतें की गई हैं।

भाजपा ने इन कलेक्टरों की शिकायत की-भाजपा ने चुनाव के दौरान पर लापरवाही एवं सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए जिन चार जिलों के खिलाफ चुनाव

आयोग में शिकायतें की हैं, उनमें नरसिंहपुर कलेक्टर रिजु बाफना, रतलाम कलेक्टर भास्कर लक्षकार और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा ने निवाड़ी के एसपी अंकित जायसवाल की भी चुनाव आयोग में शिकायत की है। इन अधिकारियों पर कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत से कम एवं धीमी गति से मतदान और केवल भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की शिकायतें हैं।

कांग्रेस ने इन कलेक्टर-एसपी की शिकायत की-कांग्रेस ने जिन कलेक्टर एवं एसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायतें की हैं, उनमें अशोकनगर कलेक्टर सुभाष द्विवेदी, सागर कलेक्टर दीपक आर्य, सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय, नरसिंहपुर कलेक्टर रिपु बाफना, दतिया कलेक्टर संदीप माकन और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, दतिया एसपी प्रदीप शर्मा और जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायतें की है। इन अधिकारियों पर कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर भाजपा को लाभ पहुंचाने की शिकायत की है।

इन अफसरों की भी शिकायत

कांग्रेस ने हरदा के जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोनिया, चांचौड़ा एसडीएम विकास कुमार आनंद, इंदौर के अपर कलेक्टर राजेश राठौर, सागर के जिला पंचायत सीईओ भव्या त्रिपाठी, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, ग्वालियर के अपर कलेक्टर विनोद भार्गव व केके सिंह, छिंदवाड़ा के अपर कलेक्टर खेमचंद वोपचे और डिप्टी कलेक्टर हेमकरण धुर्वे के साथ एएसपी अमित वर्मा, एएसपी अवधेश प्रताप सिंह, डीएसपी सौरभ आर तिवारी, डीएसपी जितेंद्र सिंह जाट, सीएसपी प्रियंका पांडे और डीएसपी अमन मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायतें की हैं।

भाजपा बना रही भितरघातियों की कुंडली

3 दिसंबर के बाद दिखाया जाएगा पार्टी से बाहर का रास्ता

***भोपाल।** मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को मतगणना के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस में किस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन इसके पहले भाजपा-कांग्रेस दोनों पार्टियां जीत और सरकार बनाने को लेकर सियासी माथापच्ची लगी हुई हैं। भाजपा ने जहां पांचवीं बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगाया है, तो कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हालांकि अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन भाजपा-कांग्रेस दोनों पार्टियों ने चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की कुंडलियां तैयार करना शुरू कर दिया है।*

हम बता दें कि भाजपा-कांग्रेस दोनों पार्टियां और उनके उम्मीदवार चुनाव के दौरान पूरे समय अपने-अपने नाराज नेताओं-कार्यकर्ताओं और भितरघातियों से जूझते नजर आए। चुनाव में कई पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं ने खुलकर पार्टी विरोधी कार्य किया, तो कई पार्टी उम्मीदवारों को भीतर-भीतर ही कमजोर करने में जुटे रहे। हालांकि भाजपा संगठन और वरिष्ठ नेताओं ने नाराज नेताओं-कार्यकर्ताओं को साधने की हर संभव कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद कई बगावती तेवर दिखाते हुए खुलकर मैदान में आ गए, तो कई नेता पार्टी में रहकर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के साथ भितरघात करते रहे। हालांकि भाजपा ने चुनाव के दौरान संगठन विरोधी कामों में संलग्र रहे, ऐसे कई नेताओं-कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तथा अब भितरघातियों की पड़ताल कर विधानसभावार सूची तैयार कराई जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मिलन भार्गव कहते हैं कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार चुनाव के दौरान भितरघात करने वाले नेता-कार्यकर्ताओं की जानकारी देंगे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से कांग्रेस में भी चुनाव के दौरान पार्टी विरोधियों में संलग्र नेताओं-कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जा रही है। इसके साथ कांग्रेस में खुलकर सामने आए विरोधियों की जानकारी कांग्रेस हाईकमान को पहुंचा दी गई है। अब पार्टी में भितरघातियों का पता लगाया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 3 दिसंबर की मतगणना के बाद पार्टी इन भितरघातियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है।

सट्टा बाजार में कांग्रेस को बढ़त, भाजपा पीछे, वीआईपी सीटों के लिए दिए नाम

भोपाल। मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत में सट्टा की एंट्री हो गई है। सट्टा बाजार ने एक बार फिर पलटी मारी है। इस बार सट्टा बाजार ने प्रदेश में कुल 230 सीटों में कांग्रेस को 116 से 120 सीट दी हैं। वहीं भाजपा को 105 से 110 सीट दी हैं। सट्टा बाजार में प्रदेश की वीआईपी सीट पर भी अपने भाव खोल दिए हैं। इससे पहले इसी सट्टा बाजार ने बीजेपी को बहुमत दिया था।

आम लोगों की बात की जाए या सियासतदारों की सबसे ज्यादा फलोदी सट्टा को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। दरअसल, यह सट्टा भी राजस्थान के फलोदी से संचालित होता है। सटोरियों के गलियारों में भाजपा के वीआईपी प्रत्याशियों के भाव भी खोले हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह समेत अन्य नाम भी शामिल हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सट्टेबाजों की दुनिया में इन सीटों पर कांग्रेस को आगे बताया गया है। इधर, वीवीआईपी सीट छिंदवाड़ा और बुदनी को लेकर सट्टा ओपन नहीं किया गया है।

इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष परिहार ने कहा कि कांग्रेस ऐसे गैरकानूनी गतिविधियों पर विचार मंथन नहीं करती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इसमें दो मत नहीं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस मध्यप्रदेश में सरकार बनाएगी।

वहीं सट्टे की दुनिया में बीजेपी को कांग्रेस से कम सीट देने पर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि किसी भी असंवैधानिक कार्यो से भाजपा का लेना देना नहीं होता। सट्टे से सत्ता तक पहुंचने की मंशा कांग्रेस जैसे संगठनों की है। इसके साथ ही उन्होंने भी भाजपा के प्रचंड बहुमत से प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का दावा किया है।

एसटीएफ की 80 टुकड़ियां संभालेंगी मोर्चा, ताकि मतगणना में न हो कोई व्यवधान

भोपाल। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग हर उपाय कर रहा है। स्ट्रांग रूम की तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बाद अब मतगणना के दिन के लिए आयोग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने जिलों में अतिरिक्त कंपनियां और सुरक्षा जवान भेजे जाएंगे। मतगणना के दिन 80 एसएएफ की कंपनियां अलग-अलग जिलों में भेजी जाएंगी। इसके अलावा रिजर्व फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। मतगणना के दिन शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए ये जवान तैनात होंगे। मतगणना के दिन किसी प्रकार की घटना-दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए फोर्स को जिलों में भेजा जाएगा।

मतगणना स्थल के लिए भी दिए निर्देश- तीन दिसंबर को मतगणना के दिन बिना आईडी के किसी व्यक्ति को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अधिकृत व्यक्ति ही काउंटिंग स्थल के आसपास आ जा सकेंगे। मतगणना स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ को एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी। सुरक्षाकर्मियों को मतगणना स्थल के आसपास असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा शहर के प्रमुख बाजारों में भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने भीड़ भाड़ वाली जगह पर जवान तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना को रोका जा सके।

स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 30 कंपनियां तैनात -आयोग ने प्रदेश के मुख्यालय स्तर पर रखी ईवीएम की सुरक्षा के लिए पहली लेयर में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 30 कंपनियां तैनात की हैं, जिनके द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है। प्रदेश के बालाघाट, डिंडौरी, मंडला, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जिलों में एक-एक कंपनी तैनात है। इसके अलावा भिंड और मुरैना में भी एक-एक कंपनी को तैनात किया गया है। बाकी जिलों में आधी आधी कंपनी यानी 40-40 जवान तैनात किए गए हैं।

पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन, की कार्यवाही की मांग

भोपाल। पूर्व मंत्री मुकेश नायक के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर पन्ना जिले में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही की शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। श्री नायक ने निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत सौंपते हुए कहा कि पन्ना जिले में 260 यात्री बसें अधिग्रहित की गई थी, साथ ही 208 चार पहिया वाहन भी चुनाव ड्यूटी में लगाये गये थे, इसके अलावा 300 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में सहयोग हेतु एकाएक ड्यूटी लगायी गई थी। पन्ना जिले में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा यात्री बसों के लगभग 500 से अधिक चालक, परिचालक और 300 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को मतदान करने के कोई प्रबंध नहीं किये गये, वे मतदान से वंचित रहें। चालक, परिचालक और अतिथि शिक्षकों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों से मतदान करने की मांग करने के बावजूद उनके साथ अनदेखी की गई, जिला निर्वाचन अधिकारियों की लापरवाही से लगभग 800 से ज्यादा व्यक्ति मताधिकार से वंचित हो गये। श्री नायक ने प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी से लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है।

जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने की मध्यप्रदेश पुलिस की सराहना

महिला एवं बाल संरक्षण के कार्यक्रमों को बताया प्रभावी कदम

भोपाल। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत संचालित महिला एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की सराहना की गई है।

भोपाल पुलिस द्वारा संचालित सामुदायिक पुलिस कार्यक्रमों में महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े प्रयोग के कारण मध्य प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर माननीय जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल सुरक्षा क्षेत्र में भोपाल पुलिस के सामुदायिक पुलिस प्रयासों के सफल संचालन के कारण जिला स्तर पर उक्त प्रयासों को आगे भी प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए समस्त थाना प्रभारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें सामुदायिक पुलिस के प्रमुख कार्यक्रम जैसे सृजन जो बालिका आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रम हैं। अधिकारियो ने बताया कि मैं हूँ अभिमन्यु जो किशोर बालको को अच्छा नागरिक बनाए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। सहयोग जो अन्य शासकीय विभागों से पुलिस के गठजोड़ से संबंधित कार्यक्रम हैं। स्टूडेंट इंटर्नशिप कार्यक्रम जो कालेज के छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने का कार्यक्रम हैं, शक्ति समिति तथा ऊर्जा हेल्प डेस्क जो घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा महिला अपराध में पुलिस की बेहतर कार्यप्रणाली विकसित करने का कार्यक्रम हैं, तथा महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े अन्य कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने से संबंधित कार्यशालाओं में आगामी माहों में होने वाली कार्यवाहियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में पूर्व में योगदान देने वाली प्रशिक्षण टीम तथा जिन थानों में अच्छा काम हुआ है उन थाना प्रभारियों की सराहना की गई, तथा अपेक्षा रखी गई कि भविष्य में उक्त कार्यक्रम और अच्छे एवं प्रभावी ढंग से संचालित होंगेद्य थाना मिसरोद, हबीबगंज, ऐशबाग, कमला नगर इत्यादि थाना में महिला एवं बाल सरंक्षण से संबंधी बेहतर कार्य हुए हैं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा तथा बाल सुरक्षा से जुड़े नए प्रयोग जैसे महिला थाने की कार्यप्रणाली में परिवर्तन तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई की कार्यप्रणाली में परिवर्तन संबंधी थानों को भी साझा किया गया। कार्यशाला में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनुराग शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस की सकारात्मक छवि निर्मित करने के लिए एवं जनता में पुलिस का विश्वास बढ़ाने के लिए, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा अपराधों को रोकने के लिए यह एक प्रभावी कदम हैं। जिसका प्रभाव समस्त पुलिस कार्यप्रणाली पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है।

इन एक्ट्रेसेस ने इमेज की परवाह किए बिना दिए इंटीमेंट सीन

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस बोल्ड सीन्स देने में बिलकुल नहीं हिचकिचाती हैं। यही वजह है कि फिल्में हों या वेब सीरीज, कई एक्ट्रेसेस ने बिना शर्म और लाज के जमकर लवमेकिंग सीन्स दिए ह। इन सीन्स की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली थी।

ईशा गुप्ता

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने फिल्मों और सोशल मीडिया पर तो बोल्डनेस दिखाई ही है लेकिन ओटीटी पर वो और ज्यादा बोल्ड हो गई थीं। आश्रम वेबसीरीज में उन्होंने बॉबी देओल के साथ जमकर सेक्स सीन्स दिए थे जिसके चलते वो काफी चर्चा में आ गई थीं। बता दे, ईशा अपने चाहने वालों के साथ सोशल मीडिया पर जुड़ी रहने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। ऐसे में अक्सर ईशा के इंस्टाग्राम पेज पर उनका सिजलिंग लुक देखने को मिलता रहता है।

कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी ने लस्ट स्टोरीज में विक्की कौशल के साथ लवमेकिंग सीन तो दिया ही था। इस फिल्म के एक सीन की वजह से वह रातों रात सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही थी। इसके अलावा भी उनका एक बोल्ड सीन विवादों में आ गया था। इसके बाद कियारा के चर्चे और तारीफ हर जगह होने लगे।

अदिति पोहनकर

बॉबी देओल के पॉप्युर वेब शो 'आश्रम' में पम्मी का किरदार को लेकर चर्चा में रहीं अदिति पोहनकर ने वेब सीरीज शी में बोल्ड किरदार निभाया था। उन्होंने कई एक्टर्स के साथ सेक्स सीन्स दिए थे। सीरीज में अदिति के काम की काफी तारीफ हुई थी। इन वेब सीरीज में इंटीमेट सीन्स देती नजर आईं अदिति सोशल मीडिया पर अक्सर खूब बोल्डनेस दिखाया करती हैं।

तमन्ना भाटिया

साउथ फिल्म अदाकारा तमन्ना भाटिया ने जब से ओटीटी पर डेब्यू किया है। उनकी दो वेबसीरीज जी करदा और लस्ट स्टोरीज 2 केवल उनके लवमेकिंग और सेक्स सीन्स के चलते चर्चा में है। इन दोनों ही वेब सीरीज में तमन्ना ने बोल्डनेस की सारी हदें पार करते हुए जमकर बोल्ड सीन दे डाले। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इस वेब सीरीज में बोल्डनेस की हदें पार करती दिखी हैं। वेब सीरीज में तमन्ना के इस लव मेकिंग सीन ने काफी सुर्खियां बटोरीं।

संजय दत्त अपने एनकाउंटर को लेकर थे परेशान,पूर्व जेल ऑफिसर का खुलासा

मनोरंजन की दुनिया के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त का फिल्मी करियर 40 साल से ज्यादा का हो गया है। संजय दत्त ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और लोगों का ध्यान खींचा है। इसके साथ ही संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में बुरा समय भी देखा जब उन्हें कुछ साल में बिताने पड़े थे। दरअसल, संजय दत्त को 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में अवैध हथियार रखने का आरोपी करार किया गया था। इसके बाद उन्हें पांच साल की सजा हुई और जेल भेजा गया था। हालांकि, संजय दत्त को अच्छे व्यवहार के कारण 8 महीने पहले रिहा कर दिया गया था। अब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा बोरवंकर ने खुलासा किया कि संजय दत्त ने जेल में किस तरह से दिन काटे थे।

संजय दत्त को जेल में नहीं मिला था स्पेशल ट्रीटमेंट

संजय दत्त जब जेल गए थे तब पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा बोरवंकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) थे। मीरान चड्ढा बोरवंकर ने साइरस ब्रोचा के पॉडकॉस्ट पर उन्होंने बताया, वह (संजय दत्त) आम तौर पर अच्छा था क्योंकि उसकी पैरोल जेल में उसके व्यवहार पर निर्भर रही थी। अगर उसने व्यवहार नहीं किया होता तो हम उसे पैरोल की अनुमति नहीं देते। वह काम भी करता था, बीड़ी और सिगरेट भी खरीद लेता था। कुल मिलाकर उसे एहसास हो गया था कि यहां उसका व्यवहार बेहतर था। मीरान चड्ढा बोरवंकर ने उन दावों का खंडन किया जिनमें कहा गया किया संजय दत्त को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था।

संजय दत्त को था अपने एनकाउंटर का डर

मीरान चड्ढा बोरवंकर ने अपनी किताब में उस समय के बारे में लिखा है, जब संजय दत्त को ऑर्थर रोड जेल से पुणे की यरवदा जेल ट्रांसफर किया जाने वाला था और वह मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर चिंतित थे। मीरान चड्ढा बोरवंकर के मुताबिक, संजय दत्त को डर था कि वह रास्ते में किसी मुठभेड़ में मारा जाएगा। उन्हें इतना डर था कि उन्हें पसीना आने लगा और उन्होंने बुखार होने की शिकायत की। संजय दत्त को बाद में एनकाउंटर के बारे में उनकी गलत धारणा के बारे में सलाह दिए जाने के बाद जेल में ट्रांसफर कर दिया गया।

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जरूर करें ये काम कभी नहीं टूटेगा रिश्ता

आजकल प्यार में दूरी रुकावट नहीं बनती हैं। जी हां वहीं रिलेशनशिप को स्ट्रॉग बनाने के लिए प्यार और भरोसा दोनों जरूरी हैं। वहीं आजकल लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहते हैं। लेकिन ये रिश्ता जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आज के समय में बनाना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपको डर है कि आपका रिश्ता टूट सकता है तो आपको कुछ तरीके अपनाने की जरूरत है। चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस वालों को क्या काम करना चाहिए?

उमीदों को लेकर करें बात-

रिश्ते में सारी चीजें क्लीयर होना बहुत जरूरी होता है। वहीं ऐसे में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी उम्मीदों और इच्छाओं पर खुलकर बात करें ऐसा करने से आपको रिश्ते में कोई गलतफहमी नहीं होगी।

भरोसा जरूर करें-

लॉन्ग डिस्टेंस में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए अगर आपको एक-दूसरे पर भरोसा नहीं है तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगा। क्योंकि भरोसा न होने पर लड़ाईयां होने लगती हैं और रिश्ता टूट जाता है।

गलतफहलमी को तुरंत खत्म करें-

कई बार रिश्ता खत्म होने का काणर गलफहमियां होती हैं। ऐसा इसलिए गलत फहमी होने पर लोग बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसके कारण कपल के बीच में दिक्कतें होने लगती हैं। जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपके के रिश्ते में कोई भी गलतफहमी है उसे दूर करें।

एक दूसरे को समय दें-

आज के समय में हर कोई बिजी है ध्यान रखें कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि।

अगर पार्टनर एक-दूसरे को समय नहीं देते हैं तो इससे दूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए एक दूसरे को समय जरूर दें।

ये होता है एचडी मेकअप जिसको लेकर दुल्हनों में क्रेज

एक शादी में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है, वो दुल्हन ही है। उनके गॉर्जियस आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक पर सभी की नजर रहती है। मगर आपको पता है कि अगर फ्लॉलेस मेकअप टू-द-पॉइंट न हो, तो इन सभी चीजों पर पानी फिर सकता है। दुल्हन अपने बड़े दिन के लिए जिस तरह का मेकअप और मेकअप आर्टिस्ट चुनती है, वह उसके लुक को खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेकअप ही है, जो दुल्हन के पूरे लुक को डिफाइन करता है। एक अच्छा और फ्लॉलेस मेकअप अपने लिए चुन पाना वाकई में एक ट्रिकी टास्क होता है। खासकर आज के समय में, जब चुनने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। इन विकल्पों में से एचडी मेकअप और एयरब्रश मेकअप ने ब्यूटी इंडस्ट्री में एक अलग ही तूफान लाया है। दुल्हनें इन दो तरह के मेकअप को लेकर कंफ्यूजन में रहती हैं। अगर आपको भी एचडी मेकअप बारे में जानना तो हम यहां जानेंगे-

एचडी मेकअप

जब आप हाई डेफिनेशन वाले कैमरा के सामने होते हैं, तो वह हमारी छोटी से छोटी कमियों को उजागर कर देता है। एचडी या हाई डेफिनेशन मेकअप उन्हीं फ्लॉज को छुपाने का काम करता है। ब्रश और ब्लेंडर का उपयोग करके मैनुअल ब्लेंडिंग के पारंपरिक तरीके से किया गया एचडी मेकअप वह है, जिसे अधिकांश सेलेब्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट पसंद करते हैं। इसकी वजह यही है कि यह बहुत ही नेचुरल, नॉन-केकी और फ्लॉलेस लुक देता है।

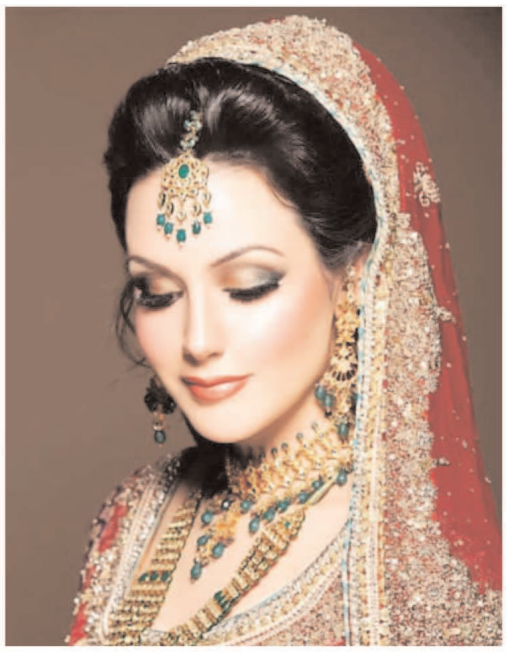

कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं इस्तेमाल?

हाई डेफिनेशन मेकअप में उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स ही इस प्रकार के मेकअप को बाकियों से अलग बनाते हैं। एचडी मेकअप के प्रोडक्ट्स हाई-एंड होते हैं और लाइट-डिफ्यूजिंग कोटिंग्स से कोटेड होते हैं,

जो लाइट को ब्लर करने में मदद करती है,जब वह रिफ्लेक्ट होती है। इसी कारण आपको स्मूथ, ट्रांसपेरेंट और फ्लॉलेस और ब्लेमिश-फ्री लुक मिल पाता है। यह आपकी खामियों को छुपाकर आपको एक नेचुरल लुक देता है

और बहुत हैवी भी नहीं लगता है।

ऐसे करें एचडी मेकअप

इसे आम मेकअप की तरह ही ट्रेडिशनल तरीके से मेकअप ब्रश और स्पंज के साथ किया जाता है। इसे करते हुए हाई-एंड प्रोडक्ट्स का ही उपयोग करना चाहिए। हां, ये प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे जरूर होते हैं। एचडी मेकअप प्रोडक्ट्स टेक्सचर में हल्के होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को भरकर चेहरे पर एक साथ न लगाएं। इससे वह अच्छी तरह ब्लेंड नहीं हो पाते और फिर आपको नेचुरल-लुकिंग फ्लॉलेस लुक नहीं मिल पाता है।

ये भी जान लें

-एचडी मेकअप में ल्यूक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, जो नेचुरल लुक देते हैं और यह आपके सभी दाग-धब्बों को अच्छी तरह छुपाने का काम करता है।

-एयरब्रश मेकअप, एचडी मेकअप से ज्यादा समय तक बरकरार रहता है और यह एक ट्रेडिशनल मेकअप तकनीक से ज्यादा जल्दी हो जाता है।

-ड्राई स्किन वाली दुल्हनों के लिए एयरब्रश मेकअप एक अच्छा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला फाउंडेशन कम क्रीमी होता है।

-एचडी मेकअप चेहरे को सॉफ्ट फोकस देता है और इसे नेचुरल और कम लेयर्ड बनाता है।

लोहे के तवे पर भी नहीं चिपकेगा डोसा

साउथ इंडियन फूड किसे पसंद नहीं होता। ये काफी हेल्दी होता है। कई लोग कोशिश करते हैं कि उनका डोसा बाजार जैसा बने पर ऐसा नहीं होता। अक्सर जब लोग लोहे के तवे पर डोसा बनाते हैं तो ये चिपक जाता है। इससे तवा भी खराब होता है और साथ में डोसे का टेस्ट भी खराब होता है। लोगों की इस परेशानी का हल हमारे पास है। दरअसल, आज की खबर में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिसको अपनाकर आप अपने डोसे को एकदम बाजार जैसा कुरकुरा बना सकते हैं। इसके लिए आपको डोसा बनाते वक्त सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।

तवे पर नहीं होनी चाहिए गंदगी

अगर आप डोसा बनाना चाह रही हैं तो सबसे पहले तवे को अच्छे से साफ कर लें। अगर इस पर तेल या गंदगी लगी रहेगी तो डोसा सही से नहीं बनेगा। इसके लिए आपको तवे को अच्छे से साफ करना चाहिए।

प्याज या आलू की मदद से करें तवे को चिकना

डोसा बनाने के लिए तवे को पहले से तैयार करना चाहिए। इसके लिए आप प्याज या आलू को आधा काट लें। अब आप कटे हुए आधे प्याज या आलू को तेल में डुबाकर इससे तवे को चिकना कर सकते हैं।

तवे को गर्म करके फिर करें ठंडा

अगर आपका डोसा लगातार चिपक रहा है तो तवे को एक बार अच्छे से गर्म करें फिर ठंडा कर लें। अब जब आप इस तवे पर डोसा बनाएंगी तो ये ज्यादा कुरकुरा बनेगा।

ना करें ये गलतियां

अगर आप डोसा बनाने जा रहीं हैं तो इसके बेटर को तुरंत फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल ना करें। डोसा बनाने के कुछ समय पहले इसे बाहर निकाल कर नॉर्मल कर लें। डोसे का बेटर तैयार करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें पानी ज्यादा ना डाला गया हो। अगर बेटर में पानी ज्यादा होगा तो डोसा फटने लगेगा।

मामला बावड़ी धसने से 36 लोगों की मौत का

हाईकोर्ट ने नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस भेजकर चार हफ्ते में मांगा जवाब

इंदौर। इंदौर के स्नेह नगर (पटेल नगर) स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। हादसा 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन हुआ था। हवन-आरती कर रहे लोग बावड़ी की स्लैब धंसकने से 36 लोगों की मौत हो गई थी।

इंदौर हाईकोर्ट ने प्रशासन के वकील से पूछा कि मार्च 2023 की घटना है, इस मामले में अब तक क्या हुआ? गिरफ्तारी, चालान क्या हुआ है? चार्जशीट पर भी सवाल किया कि क्या वो भी फाइल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में क्या निकला, उसका क्या हुआ। इधर, पीड़ित पक्ष के वकील ने घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध बताते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

मुआवजा मंदिर ट्रस्ट से वसूला क्या – हाईकोर्ट-बावड़ी हादसे में मृतकों के परिवार और घायलों को अलग-अलग मुआवजा राशि दी गई थी। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या यह राशि मंदिर ट्रस्ट से वसूली गई है। अगर नहीं तो क्यों नहीं वसूली गई। सरकार यह मुआवजा क्यों दे रही है। एफआईआर, चालान और मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी हाई कोर्ट ने दिए।

हाईकोर्ट में इस तर्क के बाद जारी हुए नोटिस-पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा- बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट को नोटिस दिया जाना चाहिए। क्योंकि आरोप और एफआईआर ट्रस्ट के ही खिलाफ है। ट्रस्ट ही जिम्मेदार है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत है। घटना के कुछ समय पहले ही प्रशासन ने ट्रस्ट को नोटिस दिया था और आप उसका जवाब देखेंगे तो वो धमकाने वाला था। ट्रस्ट ने धार्मिक भावना और अशांति का हवाला अपने जवाब में दिया था। जबकि नगर निगम ने यह माना था कि बावड़ी जर्जर है। लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी। इसके बावजूद बावड़ी पर निर्माण किया गया। नोटिस देने के तीन महीने बाद ही हादसा हो गया। इसमें राजनीतिक संलिप्तता है। इसी कारण आज तक किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है।

वकील ने आगे कहा कि मजिस्ट्रियल जांच में क्या हुआ उसका भी कोई पता नहीं है। हमें जिस बात की आशंका थी प्रशासन वो ही कर रहा है। इसके बाद प्रशासन ने शहर के तमाम कुएं और बावड़ी को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया। उन्हें (प्रशासन और ट्रस्ट) नोटिस तक जारी नहीं हुए इसलिए किसी बात से डरते ही नहीं है। फिर से ऐसी घटना ना हो इसके लिए कोई तो एक्शन हो, गाइडलाइन बने। आठ महीने बाद भी मजिस्ट्रियल जांच में क्या हुआ ये भी नहीं बता पा रहे हैं।

कमलनाथ के डीप फेक वीडियो की जांच शुरू

इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के डीप फेक वीडियो पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। कमलनाथ के 15 दिन पहले चुनावी रैली के वीडियो को एडिट कर उन्हें लाड़ली बहना योजना बंद करा दूंगा... कहते दिखाया गया था। इस मामले में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई थी। क्राइम ब्रांच ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

क्राइम ब्रांच ने बताया कि कांग्रेस की ओर से डीप फेक वीडियो को लेकर दो अलग-अलग केस दर्ज कराए गए हैं। पहले केस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वीडियो गलत तरीके से एडिट करने के बाद वायरल किया गया था। वहीं दूसरे केस में भी वीडियो को प्रदर्शित करने और जनता में कांग्रेस के खिलाफ गलत संदेश देने को लेकर स्नढ्ढक्र कराई गई थी। पुलिस दोनों मामले में अज्ञात व्यक्तियों की तलाश कर रही है। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले लाड़ली बहना योजना बंद करेंगे। जिन बहनों को पैसे मिल चुके हैं, उन सबके नाम काट देंगे और नए नाम जोड़ेंगे। नारी सम्मान योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जिनका नाम भाजपा की लाड़ली बहना योजना में नहीं होगा। ये हमारा वचन है। ये कमलनाथ का वचन है।

कांग्रेस ने कहा- भाजपा आईटी सेल कर रही बदनाम-कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने कहा कि देश में,ढ्ढ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डीप फेक का जितना ज्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल भाजपा की आईटी सेल कर रही है, उतना और कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा आईटी सेल कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए लगातार इस तरह के काम कर रही है। मप्र चुनाव में कमलनाथ का एक डीप फेक वीडियो प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें वो लाड़ली बहना योजना को बंद करने की बात करते हुए दिख रहे हैं। जब वो वीडियो सामने आया तो इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का इन अपराधियों को समर्थन है। इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी निमिष अग्रवाल ने कहा कि 15 दिन पहले एक चुनावी रैली के वीडियो को डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में शिकायत मिली थी। एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।

शासकीय आंकड़ों में डेंगू से एक भी मौत नहीं, जबकि हो चुकी हैं आठ

इंदौर। डेंगू से एक और लोगों को राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड में आ रहे अंतर वास्तविक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या आठ है, लेकिन शहर के एक निजी अस्पताल ने दावा किया है कि डेंगू के दस से अधिक मरीज भर्ती हुए हैं और इसी तरह के आंकड़े अन्य न अस्पताल में भी दिख रहे हैं। जिले. भर के अस्पतालों में डेंगू के 8 हे मरीजों की मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड में एक र भी मौत नहीं हुई। जिला मलेरिया अधिकारी डा. दौलत पटेल के मुताबिक अब तक कुल 443 मरीज पाजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से आठ मरीजों का इलाज चल रहा है। निजी अस्पताल रैपिड टेस्ट और घटती प्लेटलेट्स के आधार पर मरीजों की गिनती करते हैं। हम मैक एलिसा जांच को ही सहीं मानते हैं।

कुछ संदिग्ध मौतें- देपालपुर निवासी 26 वर्षीय युवक की 25 नवंबर को अरबिंदो अस्पताल में मौत हो गई। उसका डेंगू का इलाज़ चल रहा था। बड़गोंद गांव निवासी 27 वर्षीय युवक की 22 नवंबर को निजी अस्पताल में मौत हो गई। चंदर गांव के 18 वर्षीय युवक की भी बीमारी से मौत हो गई।

चोरों को ब्लैकमेल करने के चक्कर में चोरी का हुआ पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

इंदौर। चंदन नगर थाना पुलिस ने चोरों की गैंग पकड़ी है। चोर आपस में ही झगड़ रहे थे। पुलिस ने जब पकड़ा तो लाखों की चोरी कबूल ली। चोरों को ब्लैकमेल करने के चक्कर में सभी पकड़ा गए।

एसीपी नंदनी शर्मा के मुताबिक, चंदन नगर थाना क्षेत्र में सूने घरों में चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने मामले में जुनैद मंजू अली, भय्यू शाहनवाज खान, छोटू उर्फ फरहान खान, तौहिद उर्फ बिल्लू सांडा को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने सोना-चांदी और अन्य सामान चुराया था। टीआइ इंद्रमणि पटेल के मुताबिक, आरोपितों के सीसीटीवी फुटेज मिले थे। पुलिसकर्मियों ने वाट्सएप ग्रुप पर फुटेज साझा किए थे। आरोपित जुनेद ने फुटेज देखकर चोरों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने चोरों से चुराया सामान ले लिया। वह बेचने की कोशिश कर रहा था और पुलिस को खबर मिल गई।

एक के बाद एक तीन लोगों से मोबाइल लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार

इंदौर। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने लोगों की मदद से तीन बदमाशों को पकड़ा है। आरोपी इलाके से ही एक स्टूडेंट का मोबाइल लेकर भागे थे। इसके पहले वे दो लूट कर चुके थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनसे और लूट की जानकारी भी मिली है।

भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक प्रियव्रत पाल राठौर निवासी कौशल्यापुरी चितावद की शिकायत पर आरोपी तरुण पुत्र धीरज शिंदे निवासी कुम्हार भट्टा पालदा, लक्की पुत्र सर्वेश भारती निवासी पवनपुरी और विकास उर्फ टडेल पुत्र कमल खेड़े पर केस दर्ज किया है।

प्रियव्रत के मुताबिक वह मोबाइल पर बात कर करते हुए पैदल जा रहा था। इसी दौरान लुटेरों ने झपट्?टा मारकर मेरे हाथ से मोबाइल लूट लिया। आरोपी भागकर आजाद नगर इलाके से भंवरकुआ वाले इलाके में घुसे। इससे पहले वे पंवार जिम और एक पेट्रोल पंप के यहां भी दो लोगों के मोबाइल लूट चुके थे। लेकिन प्रियव्रत के साथ लूट होने के बाद अन्य राहगीर साथ आए। सभी ने बदमाशों का पीछा किया। और उन्हें राजीव गांधी चौराहे पर दबोच लिया। पुलिस अफसरों के मुताबिक आरोपी पुराने लुटेरे हैं। आरोपियों से लूट के तीन मोबाइल जब्त किये गए हैं।

मोबाइल लूटकर भाग रहा था ई स्कूटर से टकराया

इंदौर के एमआईजी पुलिस ने भी लोगों की मदद से एक लुटेरे को पकड़ा है। वह बाइक से एक व्यक्ति का मोबाइल लेकर भागने के दौरान ई स्कूटर से जा टकराया। एमआईजी पुलिस के मुताबिक गोविंद सोमानी निवासी अशोक नगर एअरपोर्ट रोड की शिकायत पर पुलिस ने गीतेश पटेल को पकड़ा है। गोविंद ने बताया कि वह पाटनीपुरा मेनरोड पर इंफोटेक एकेडमी के पास खड़े थे। इसी दौरान आरोपी ने बाइक से आकर उनके मोबाइल पर झपट्?टा मारा। मोबाइल सड़क पर गिरने के बाद उन्होंने आरोपी के पीछे दौड़ लगाई तो वह जल्दबाजी में सामने से आ रही एक ई स्कूटर में बाइक सहित घुसकर घायल हो गया।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्प्लेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)